

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं० B.S.T 59 बस्ती, वर्ष 46 अंक 18 मंगलवार 6 अक्टूबर 2024 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या-फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ 4मूल्य3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

डायट में शुरू हुआ 204 शिक्षकों का गणित कित प्रशिक्षण



—भारतीय बस्ती संवाददाता— बस्ती। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में सोमवार को जपद के आठ विकासखण्डों के 204 शिक्षकों के तीन दिवसीय गणित कित प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। उदघाटन सत्र को संबोधित करते हुए डायट प्रचार्य संजय कुमार शुक्ल ने कहा कि शिक्षकों की चुनौती हमारे सामने है। मौजूदा परिचय को देखते हुए शिक्षा को रोकच बनाने से लेकर, खेल की गतिविधियों को विस्तार देने, कमजोर बच्चों की मदद करने के साथ ही शिक्षा को आधुनिकता के कोशरों से जोड़ने की आवश्यकता है। कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में इस प्रशिक्षण से गणित विषय की रोकचता तथा अग्रिम से मूल की तैयारी करने में मदद मिलेगी। गणित कित के माध्यम से बच्चे आकृतियों, संख्या, गुणन घटक, संख्या आदि विषयवस्तु को ठीक तरह से सीख सकेंगे। प्रशिक्षण को नेडस लक्षित अतीवृद्धि खान ने कहा कि गणित कित में छात्रों के मानस संख्या प्रक्रिया, आकृति, पैटर्न आदि अक्षाण्वार विकसित करने के लिए भरपूर सामग्री है जिसका लाभ छात्रों को शिक्षा के दौरान दिया जा सकता है। संवर्धनदाता हरेंद्र यादव, बालमुकुंद और अनूप सिंह ने प्रशिक्षण के पहले दिन गणित कित की नवावरी शिक्षण विधियां, समेकन, शिक्षण के दौरान कित का प्रभावी उपयोग, शिक्षण योजना का निर्माण आदि विषय पर विस्तृत जानकारी दिया। इस अवसर पर डॉ. गोविन्द प्रसाद, राशिदरसन त्रिपाठी, सरिता चौधरी, रवि पटेल, नन्दन चौधरी, रविनाथ त्रिपाठी, इमरान खान, कल्याण पाण्डेय, कुलदीप चौधरी, अमनरसेन, विवेक कान्त पाण्डेय, कुलदीप सिंह, दीपक मिश्र, लखकृष्ण त्रिपाठी, गोपाल उद्वे, सविन पाण्डेय, मधुसूदन तिवारी, अरुण उद्वे, शिव कुमार त्रिपाठी, रमनदीप शर्मा, विवेक कुमार, मेराज अहमद, विजय चौधरी, निशांत मिश्र, मो. सलाम, संजय, लाल महेश मौर्य, शशिकांता आदि उपस्थित रहे।

शिक्षायात्रा के निस्तारण का निर्देश

—भारतीय बस्ती संवाददाता— बस्ती। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में सोमवार को जपद के आठ विकासखण्डों के 204 शिक्षकों के तीन दिवसीय गणित कित प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। उदघाटन सत्र को संबोधित करते हुए डायट प्रचार्य संजय कुमार शुक्ल ने कहा कि शिक्षकों की चुनौती हमारे सामने है। मौजूदा परिचय को देखते हुए शिक्षा को रोकच बनाने से लेकर, खेल की गतिविधियों को विस्तार देने, कमजोर बच्चों की मदद करने के साथ ही शिक्षा को आधुनिकता के कोशरों से जोड़ने की आवश्यकता है। कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में इस प्रशिक्षण से गणित विषय की रोकचता तथा अग्रिम से मूल की तैयारी करने में मदद मिलेगी। गणित कित के माध्यम से बच्चे आकृतियों, संख्या, गुणन घटक, संख्या आदि विषयवस्तु को ठीक तरह से सीख सकेंगे। प्रशिक्षण को नेडस लक्षित अतीवृद्धि खान ने कहा कि गणित कित में छात्रों के मानस संख्या प्रक्रिया, आकृति, पैटर्न आदि अक्षाण्वार विकसित करने के लिए भरपूर सामग्री है जिसका लाभ छात्रों को शिक्षा के दौरान दिया जा सकता है। संवर्धनदाता हरेंद्र यादव, बालमुकुंद और अनूप सिंह ने प्रशिक्षण के पहले दिन गणित कित की नवावरी शिक्षण विधियां, समेकन, शिक्षण के दौरान कित का प्रभावी उपयोग, शिक्षण योजना का निर्माण आदि विषय पर विस्तृत जानकारी दिया। इस अवसर पर डॉ. गोविन्द प्रसाद, राशिदरसन त्रिपाठी, सरिता चौधरी, रवि पटेल, नन्दन चौधरी, रविनाथ त्रिपाठी, इमरान खान, कल्याण पाण्डेय, कुलदीप चौधरी, अमनरसेन, विवेक कान्त पाण्डेय, कुलदीप सिंह, दीपक मिश्र, लखकृष्ण त्रिपाठी, गोपाल उद्वे, सविन पाण्डेय, मधुसूदन तिवारी, अरुण उद्वे, शिव कुमार त्रिपाठी, रमनदीप शर्मा, विवेक कुमार, मेराज अहमद, विजय चौधरी, निशांत मिश्र, मो. सलाम, संजय, लाल महेश मौर्य, शशिकांता आदि उपस्थित रहे।

प्रधानाचार्य शानु एन्टोनी को मातृ शोक

—भारतीय बस्ती संवाददाता— बस्ती। राजन हरेंद्र नेमल एन्टोनी के प्रधानाचार्य शानु एन्टोनी की बयोकृत माता श्रीमती सुविधाया जोगेश्वर का उनका केसर पाण्डेय के मुक गंध में निवृत्त हो गया। सोमवार को राजन हरेंद्र नेमल एन्टोनी ने श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर विद्यालय परिवार और छात्रों ने दो मिनट का मौन रखकर श्रीमती इतिवामा जोषकर को श्रद्धा पुष्प अर्पित किया गया। प्रबन्ध निदेशिका शिक्षा वसुदेवी, कार्यकारी निदेशक संजय पाण्डेय के साथ ही शिक्षकों ने दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि संसार में सब बड़ा कोई नहीं।

शिक्षायात्रा के निस्तारण का निर्देश

—भारतीय बस्ती संवाददाता— बस्ती। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में सोमवार को जपद के आठ विकासखण्डों के 204 शिक्षकों के तीन दिवसीय गणित कित प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। उदघाटन सत्र को संबोधित करते हुए डायट प्रचार्य संजय कुमार शुक्ल ने कहा कि शिक्षकों की चुनौती हमारे सामने है। मौजूदा परिचय को देखते हुए शिक्षा को रोकच बनाने से लेकर, खेल की गतिविधियों को विस्तार देने, कमजोर बच्चों की मदद करने के साथ ही शिक्षा को आधुनिकता के कोशरों से जोड़ने की आवश्यकता है। कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में इस प्रशिक्षण से गणित विषय की रोकचता तथा अग्रिम से मूल की तैयारी करने में मदद मिलेगी। गणित कित के माध्यम से बच्चे आकृतियों, संख्या, गुणन घटक, संख्या आदि विषयवस्तु को ठीक तरह से सीख सकेंगे। प्रशिक्षण को नेडस लक्षित अतीवृद्धि खान ने कहा कि गणित कित में छात्रों के मानस संख्या प्रक्रिया, आकृति, पैटर्न आदि अक्षाण्वार विकसित करने के लिए भरपूर सामग्री है जिसका लाभ छात्रों को शिक्षा के दौरान दिया जा सकता है। संवर्धनदाता हरेंद्र यादव, बालमुकुंद और अनूप सिंह ने प्रशिक्षण के पहले दिन गणित कित की नवावरी शिक्षण विधियां, समेकन, शिक्षण के दौरान कित का प्रभावी उपयोग, शिक्षण योजना का निर्माण आदि विषय पर विस्तृत जानकारी दिया। इस अवसर पर डॉ. गोविन्द प्रसाद, राशिदरसन त्रिपाठी, सरिता चौधरी, रवि पटेल, नन्दन चौधरी, रविनाथ त्रिपाठी, इमरान खान, कल्याण पाण्डेय, कुलदीप चौधरी, अमनरसेन, विवेक कान्त पाण्डेय, कुलदीप सिंह, दीपक मिश्र, लखकृष्ण त्रिपाठी, गोपाल उद्वे, सविन पाण्डेय, मधुसूदन तिवारी, अरुण उद्वे, शिव कुमार त्रिपाठी, रमनदीप शर्मा, विवेक कुमार, मेराज अहमद, विजय चौधरी, निशांत मिश्र, मो. सलाम, संजय, लाल महेश मौर्य, शशिकांता आदि उपस्थित रहे।

बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना त्याग पत्र देने के बाद भारत पहुंची



बाका (आमा) बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर मंचे बवाल के बाद हालत बेकाबू हो गए हैं। हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उपद्रवियों की भीड़ ने पीएम आवास पर ही हमला बोल दिया है। शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़कर भारत आ चुकी हैं। अब वह दिल्ली से लंदन की पहाड़ट लेने की तैयारी में हैं। इस बात बांग्लादेश की सेना ने कमान संभाल ली है और अंतरिम सरकार के गठन की तैयारी है। सेना के मुखिया बकार-उज-जमाल ने कहा कि सारा का हस्तगतण चल रहा है। एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। सभी हत्याओं की जांच की जाएगी। सेना पर जनता

रालोद की बैठक में पदाधिकारियों की घोषणापत्रों में शामिल होने वालों का किया स्वागत



कार्यक्रम के अनुरूप सचर्च तैयार करें। कहा कि किसानों, मौजवानों के हितों के लिये पार्टी का रचनात्मक संघर्ष जारी रहेगा। बताया कि पार्टी का जिला कार्यक्रम समलेन कर्नाली कि-गा-मसा क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। रालोद के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य आम प्रकाश चौधरी ने कहा कि संगठन की मजबूती से ही देशों की प्राप्ति संभव है। इस दिशा में निरन्तर सक्रियता बनाये रखना ज़रूरी। रालोद की मासिक बैठक में अपना दल एन के पदाधिकारियों प्रमोद चौधरी, रोसा चन्द मिरी, राम राजेन द्विवेदी, इफ़्फ़ान अहमद, निसार अहमद, सदीप पटेल, राकेश कुमार विश्वकर्मा, शिव कुमार वर्मा, रवीन्द्र चौधरी रालोद में शामिल हुए। प्रदेश महासचिव एवं सरस्वती प्रमोदी अरुणेंद्र पटेल ने उन्हें स्वस्वता दिलाया। मुख्य रूप से मजदूर अख्यक सुरेंद्र चौधरी, चन्द्रिका प्रसाद, महेंद्र चौधरी, मोतीलाल, इन्द्र बहादुर यादव, साहेन्द्र फारूकी, श्रीराम मौर्य, अशरफ अली, प्रदीप चौधरी, के साथ ही रालोद के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता शामिल रहे।

रामनगर विकास खण्ड की बैठक का प्रस्ताव पारित नाम वशिष्ठ नगर करने का प्रस्ताव पारित

—भारतीय बस्ती संवाददाता— बस्ती। सोमवार को विकास खण्ड रामनगर समामार में हुए क्षेत्र पंचायत बैठक में जनपद बस्ती का नाम वशिष्ठ नगर करने हेतु क्षेत्र पंचायत रामनगर में प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित किया गया। क्षेत्र पंचायत मनरेगा योजना वर्ष 2024-25 की अनुप्रकृष व क्षेत्र पंचायत निधि वर्ष 2024-25 की अनुप्रकृष कार्ययोजना अनुमोदित की गयी। ब्लाक प्रमुख वाशकान्त सिंह ने एक पैड में का नाम जो. प्रमनदीपों का आवाहन है इस क्रम में सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वे सभी अपने अपने ग्राम पंचायतों में अपना मो के नाम एक पैड लगाने के साथ ही उसको संश्लिष्ट करें। मुख्यमंत्री की अति. मन्वलयकी योजना निराश्रित महिला आवास योजना और विद्यालय आवास योजना अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को लाभ दिलाते हेतु सभी सदस्यों से विकास विभाग का आग्रह किया गया। पशुपालन विभाग से आवे 30 सौ संतोष कुमार श्रीवास्तव द्वारा पशुपालन सम्बन्धी अनेक योजनाओं तथा उरुका लामा कैसे ले सकते हैं के बारे में जानकारी दी गयी। पंचायत विभाग के योजनाओं में बारे में प्रमोद कुमार राम विकास अधिकारी द्वारा जानकारी दी गयी।

फाइलेरिया उन्मूलन के लिये कार्यशाला



—भारतीय बस्ती संवाददाता— बस्ती। जिला उपप्रताल के समामार में मुख्य चिकित्साधिकारी रामशरर दूरे की अध्यक्षता में नीडिया ड्रीगिण संवेदकरीण कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्साधिकारी रामशरर दूरे ने बताया कि फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 10 अगस्त से 2 सितम्बर तक चलेगा। बताया कि फाइलेरिया मच्छर के काटने से होने वाला यह संक्रामक रोग है इससे बचाव के लिए सरकारी द्वारा लोगों को मुफ्त दवा दी जा रही है एक पखवार तक बने बाल फाइलेरिया मुक्ति अभियान की सफलता के लिये आनाआनवाड़ी एवं प्रशिक्षित बायोलेटिसर को लगाना गये हैं। डी.एन.आई.ए अंसारो में बताया कि कार्यक्रम में कुल 2305 लोगों की टीम बनायी गयी है प्रत्येक टीम में 2 लोग रहेंगे इसमें एक डॉक्टर की 387 सुपरवाइजर भी लगाए गए हैं (जो घर घर जाकर दो वक के ऊपर के सभी लोगों को दवा की सुराकर देंगे 12 से पांच वर्ष के बच्चों को) डी.ई.सी.ए एवं एन्डोजलोल की एक एक गोली 6 से 14 साल के

हाइवे पर ओवर ब्रिज निर्माण का मागः भेजा ज़ापन



—भारतीय बस्ती संवाददाता— बस्ती। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में सोमवार को जपद के आठ विकासखण्डों के 204 शिक्षकों के तीन दिवसीय गणित कित प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। उदघाटन सत्र को संबोधित करते हुए डायट प्रचार्य संजय कुमार शुक्ल ने कहा कि शिक्षकों की चुनौती हमारे सामने है। मौजूदा परिचय को देखते हुए शिक्षा को रोकच बनाने से लेकर, खेल की गतिविधियों को विस्तार देने, कमजोर बच्चों की मदद करने के साथ ही शिक्षा को आधुनिकता के कोशरों से जोड़ने की आवश्यकता है। कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में इस प्रशिक्षण से गणित विषय की रोकचता तथा अग्रिम से मूल की तैयारी करने में मदद मिलेगी। गणित कित के माध्यम से बच्चे आकृतियों, संख्या, गुणन घटक, संख्या आदि विषयवस्तु को ठीक तरह से सीख सकेंगे। प्रशिक्षण को नेडस लक्षित अतीवृद्धि खान ने कहा कि गणित कित में छात्रों के मानस संख्या प्रक्रिया, आकृति, पैटर्न आदि अक्षाण्वार विकसित करने के लिए भरपूर सामग्री है जिसका लाभ छात्रों को शिक्षा के दौरान दिया जा सकता है। संवर्धनदाता हरेंद्र यादव, बालमुकुंद और अनूप सिंह ने प्रशिक्षण के पहले दिन गणित कित की नवावरी शिक्षण विधियां, समेकन, शिक्षण के दौरान कित का प्रभावी उपयोग, शिक्षण योजना का निर्माण आदि विषय पर विस्तृत जानकारी दिया। इस अवसर पर डॉ. गोविन्द प्रसाद, राशिदरसन त्रिपाठी, सरिता चौधरी, रवि पटेल, नन्दन चौधरी, रविनाथ त्रिपाठी, इमरान खान, कल्याण पाण्डेय, कुलदीप चौधरी, अमनरसेन, विवेक कान्त पाण्डेय, कुलदीप सिंह, दीपक मिश्र, लखकृष्ण त्रिपाठी, गोपाल उद्वे, सविन पाण्डेय, मधुसूदन तिवारी, अरुण उद्वे, शिव कुमार त्रिपाठी, रमनदीप शर्मा, विवेक कुमार, मेराज अहमद, विजय चौधरी, निशांत मिश्र, मो. सलाम, संजय, लाल महेश मौर्य, शशिकांता आदि उपस्थित रहे।

रामनगर विकास खण्ड की बैठक का प्रस्ताव पारित नाम वशिष्ठ नगर करने का प्रस्ताव पारित

—भारतीय बस्ती संवाददाता— बस्ती। सोमवार को विकास खण्ड रामनगर समामार में हुए क्षेत्र पंचायत बैठक में जनपद बस्ती का नाम वशिष्ठ नगर करने हेतु क्षेत्र पंचायत रामनगर में प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित किया गया। क्षेत्र पंचायत मनरेगा योजना वर्ष 2024-25 की अनुप्रकृष व क्षेत्र पंचायत निधि वर्ष 2024-25 की अनुप्रकृष कार्ययोजना अनुमोदित की गयी। ब्लाक प्रमुख वाशकान्त सिंह ने एक पैड में का नाम जो. प्रमनदीपों का आवाहन है इस क्रम में सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वे सभी अपने अपने ग्राम पंचायतों में अपना मो के नाम एक पैड लगाने के साथ ही उसको संश्लिष्ट करें। मुख्यमंत्री की अति. मन्वलयकी योजना निराश्रित महिला आवास योजना और विद्यालय आवास योजना अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को लाभ दिलाते हेतु सभी सदस्यों से विकास विभाग का आग्रह किया गया। पशुपालन विभाग से आवे 30 सौ संतोष कुमार श्रीवास्तव द्वारा पशुपालन सम्बन्धी अनेक योजनाओं तथा उरुका लामा कैसे ले सकते हैं के बारे में जानकारी दी गयी। पंचायत विभाग के योजनाओं में बारे में प्रमोद कुमार राम विकास अधिकारी द्वारा जानकारी दी गयी।

जयन्ती पर यादव गये प्रखर समाजवादी छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र

—भारतीय बस्ती संवाददाता— बस्ती। समाजवादी चिन्तक अनूप पूर्व केंद्रीय मंत्री जनेश्वर मिश्र को उनकी जयन्ती पर याद किया गया। सोमवार को समाजवादी पद कार्यलय में बस्ती सदर विधाकर एवं सभा जिलाध्यक्ष महेन्द्रनाथ यादव के संयोजन में आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने उन्हें याद किया। महेन्द्रनाथ यादव ने कहा कि वे आखिरी सांस तक समाजवादी थे और उन्हें समाजवाद की चली फिल्टी पाशाला कहा जाय। राजनीति में उन्होंने सदैव सादगी बनाये रखी और कार्यकर्ताओं को सर्वोच्च समान दिया। युवा पीढ़ी को उनके जीवन संघर्ष और राजनीतिक उददेश्य से प्रेरण लेनी चाहिये। कहा कि आज देश में साम्प्रदायिक धुंकीकरण हो रहा है ऐसे में हमें अपने गंगा जमुनी तटवीर को बचाये रखना होगा, यही जनेश्वर मिश्र जैसे महान नेता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। समाजवादी चिन्तक चन्द्रपूर मिश्र, जायदे पिण्डारी, मो. वल्लभ, समीर चौधरी, अमील अहमद, दयाशंकर मिश्र, रामनरेश यादव, रामशंकर निराला, विपिन विवादी, पंकज मिश्र, राधेन्द्र सिंह, देवेंद्र श्रीवास्तव, अरविन्द सोनकर, हरेश आदि ने जनेश्वर मिश्र को गन्तू करते हुवे कहा कि जनेश्वर मिश्र के प्रभाव से बड़ी संख्या में युवा जुड़े और समाजवादी विचारधारा को देश भर में स्वीकारयित्त मिली। वक्ताओं ने मुस्लिमों को साझा करते हुवे कहा कि बस्ती

समाजवाद की पाठशाला थे जनेश्वर मिश्र— महेन्द्रनाथ यादव

जनेश्वर मिश्र का विशेष लगाव था, वे जब आते तो सबसे मिलने की कोशिश करते। कहा कि कार्यकर्ताओं के लिये उनके मन में विशेष सम्मान था। सादगी उनके राजनीतिक विरोधालो को सर्वोच्च समान दिया। युवा पीढ़ी को उनके जीवन संघर्ष और राजनीतिक उददेश्य से प्रेरण लेनी चाहिये। कहा कि आज देश में साम्प्रदायिक धुंकीकरण हो रहा है ऐसे में हमें अपने गंगा जमुनी तटवीर को बचाये रखना होगा, यही जनेश्वर मिश्र जैसे महान नेता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। समाजवादी चिन्तक चन्द्रपूर मिश्र, जायदे पिण्डारी, मो. वल्लभ, समीर चौधरी, अमील अहमद, दयाशंकर मिश्र, रामनरेश यादव, रामशंकर निराला, विपिन विवादी, पंकज मिश्र, राधेन्द्र सिंह, देवेंद्र श्रीवास्तव, अरविन्द सोनकर, हरेश आदि ने जनेश्वर मिश्र को गन्तू करते हुवे कहा कि जनेश्वर मिश्र के प्रभाव से बड़ी संख्या में युवा जुड़े और समाजवादी विचारधारा को देश भर में स्वीकारयित्त मिली। वक्ताओं ने मुस्लिमों को साझा करते हुवे कहा कि बस्ती

विश्व हिंदू महासंघ पदाधिकारियों ने डीएम को भेंट किया पराक्रम पत्रिका:मासिक बैठक में हिन्दुत्व की रक्षा पर विमर्श



—भारतीय बस्ती संवाददाता— बस्ती। सोमवार को विश्व हिंदू महासंघ जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह की अध्यक्षता में मासिक बैठक शिविर कार्यलय सुल्हानी टावर पर सम्पन्न हुई। बैठक को सम्बोधित करते हुवे अखिलेश सिंह ने कहा कि हिन्दू समाज के आन-मान की रक्षा के लिये निरन्तर रचनात्मक प्रयासों को जारी रखने की जरूरत है। उन्होंने पदाधिकारियों से कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रियता बनाये रखें और ध्यान रहे कि किसी हिन्दू परिवार का उत्पीडन न होने पाये। बैठक के बाद विश्व हिंदू महासंघ पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह के नेतृत्व में जिलाधिकारी रवीश गुप्ता से मंत्रकर उन्हे महासंघ की पराक्रम पत्रिका भेंट किया। महासंघ जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह ने जिलाधिकारी रवीश गुप्ता को महासंघ द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुवे कहा कि गोकेशी पर नियंत्रण कराना ज़रूरी। मासिक बैठक और जिलाधिकारी

सेवा निवृत्त कर्मचारी एसोसिएशन की बैठक में मुद्दों पर बनी रणनीति

—भारतीय बस्ती संवाददाता— बस्ती। सोमवार को सेवा निवृत्त कर्मचारी एसोसिएशन की मासिक बैठक जिलाध्यक्ष नरेंद्र बहादुर उपाध्याय की अध्यक्षता में प्रेम बल्लभ समामार में सम्पन्न हुई। संबालन श्यामकर सोनी ने किया। बैठक को सम्बोधित करते हुवे जिलाध्यक्ष नरेंद्र बहादुर उपाध्याय ने बताया कि एसोसिएशन लगातार सेवा निवृत्त कर्मचारियों के हितों के लिये संघर्ष कर रहा है। बैठक में राशिदरसन पेंशन को चरणी 10 वर्ष बाद न किये जाने, पेंशन को आयकर की सीमा से बाहर किये जाने, उम्र 65, 70 और 75 वर्ष से 5, 10, 15 प्रशिक्षण पेंशन में बढ़ोतरी, रेलवे कर्मचारी में बरिष्ठ नागरिकों के लिये छूट बल्लभ किये जाने, पुरानी पेंशन बहाली को कैशलेस योजितना, कोराना का क्रीज डोरा जारी करने आदि का मुद्दा ज्ञाने जाय। निर्णय लिया गया कि मांग न माने। निर्णय है उरु एसोसिएशन संघर्ष करने को बल्लभ होगा। ई देवी प्रसाद शुक्ल, राम चन्द्र शुक्ल, चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, रामनाथ, अनरग्रामा सिंह, राधेशंकर तिवारी, प्रमोदरसन लाल अरि भेमाकिर, अमरनाथ सिंह, सुखेश कुमार द्वारा प्रेम बल्लभ विचार निराकरण कराया गया। निश्चित रूप से इसके सकारात्मक यत्न

वरिष्ठ नागरिकों के लिये रेल सुविधा में छूट बहाल करे सरकार— नरेंद्र बहादुर

सामने आयेगे। वक्ताओं की सम्प्रसादों को निस्तारण के लिये एसोसिएशन लगातार संघर्षशील है। वक्ताओं 50 प्रशिक्षण पेंशन में बढ़ोतरी, रेलवे कर्मचारी में बरिष्ठ नागरिकों के लिये छूट बल्लभ किये जाने, पुरानी पेंशन बहाली को कैशलेस योजितना, कोराना का क्रीज डोरा जारी करने आदि का मुद्दा ज्ञाने जाय। निर्णय लिया गया कि मांग न माने। निर्णय है उरु एसोसिएशन संघर्ष करने को बल्लभ होगा। ई देवी प्रसाद शुक्ल, राम चन्द्र शुक्ल, चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, रामनाथ, अनरग्रामा सिंह, राधेशंकर तिवारी, प्रमोदरसन लाल अरि भेमाकिर, अमरनाथ सिंह, सुखेश कुमार द्वारा प्रेम बल्लभ विचार निराकरण कराया गया। निश्चित रूप से इसके सकारात्मक यत्न

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"-वेडेल फिलिपा

भारतीय बस्ती

बस्ती 6 अगस्त 2024 मंगलवार

सम्पादकीय

मुकदमों का बढ़ता बोझ

लोकतंत्र के चार स्तंभों में से एक न्यायपालिका काफ़ी दबाव में है। अदालतों में मुकदमों का अंबार लगा हुआ है। देश के सर्वोच्च न्यायालय से लेकर विभिन्न अदालतों में मुकदमों का बोझ इस कदर हावी है कि न्याय की रफ़्तार धीमी से धीमी होती जा रही है। अदालतों पर बढ़ते बोझ की समस्या की तस्वीर आंकड़ों के साथ पेश की जाए तो आम आदमी न्याय की आस ही छोड़ बैठेगा। आंकड़ों के हवालों से बात की जाए तो देश के विभिन्न अदालतों में अभी जितने मुकदमे लंबित हैं, सिर्फ़ उनकी ही दंग से सुनवाई की जाए, तो उनका निपटारा होने में लगभग 25 सालों का समय लगेगा। आसानी से समझा जा सकता है कि अगले 25 सालों में अदालतों में और कितने नए मुकदमे आएंगे। इस तरह से जो लंबित मुकदमे हैं, उन्हें निपटाने में 25 वर्ष की जगह और भी लंबा समय लग सकता है। साफ़ है कि एक ओर तो न्यायपालिका पर मुकदमों का बोझ लदा है, दूसरी ओर उसके जरूरत पर न्यायाधीश भी नहीं हैं। देश की न्याय प्रक्रिया को यदि दुरुस्त करना है तो एक साथ दो मोर्चों पर काम करने की जरूरत है।

देश के प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की इस स्वीकारोक्ति ने हर संबन्धशील भारतीयों के मन को छुआ कि अदालतों में लंबे समय से लंबित मामलों से तंग आकर लोग बस समझौता करना चाहते हैं। वैसे तो इस बात को सभी महसूस करते हैं लेकिन न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष पर आसून मुख्य न्यायाधीश की स्वीकारोक्ति के गहरे निहितार्थ हैं। उन्होंने कहा कि लोग अदालतों में मुकदमों के लंबे खिंचने से इतने त्रस्त हो जाते हैं कि किसी तरह समझौता करके पिंड छुड़ाना चाहते हैं। न्यायमूर्ति ने स्वीकारा कि एक जज के रूप में यह स्थिति हमारे लिए चिंता का विषय होनी चाहिए। उन्होंने माना कि इन स्थितियों में किसी तरह का समझौता समाज में पहले से व्याप्त असमानता को ही दर्शाता है। उन्होंने वादों के शीर्ष निपटान में लोक अदालतों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी स्वीकार किया। निरसंह, गाहे-बग़ाहे न्यायपालिका, कार्यपालिका व विधायिका द्वारा न्याय मिलने में होने वाली देरी को लेकर चिंता जरूर जातीय जाती है, लेकिन इस जटिल समस्या के समाधान की दिशा में बदलावकारी प्रयास होते नजर नहीं आते। जिसके चलते तारीख पर तारीख का सिलसिला चलता ही रहता है। न्याय के इंजनार में कई-कई पीढ़ियां अदालतों के चक्कर काटती रह जाती हैं। देश में शीर्ष अदालत, उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में मुकदमों का अंबार निश्चित रूप से न्यायिक व्यवस्था के लिये असहज स्थिति है। बताया जाता है कि देश में तीनों स्तरों पर करीब पांच करोड़ मामले लंबित हैं। निश्चित ही यह न्यायिक व्यवस्था के लिये एक गंभीर चुनौती है। जिसके बावत देश के नीति-नियंत्रणों को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

निरसंह, भारत दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी के अनुपात में पर्याप्त न्यायाधीशों व न्यायालयों की उपलब्धता नहीं है। निश्चित रूप से न्याय का मतलब न्याय मिलने जैसा होना चाहिए। न्याय समाज में महसूस भी होना चाहिए। देश में न्याय की प्रक्रिया सहज व सरल तथा आम आदमी की पहुँच वाली होनी चाहिए। राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं में न्यायिक प्रक्रिया की मांग लंबे समय से की जाती रही है। इस दिशा में कुछ प्रयास हुए भी हैं लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जिससे तारीख पर तारीख का सिलसिला थम सके। जिसके लिये जरूरी है कि अदालती मामलों का तय समय सीमा में निपटारा किया जाना सुनिश्चित हो। उम्मीद की जा रही है कि हाल ही में लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद स्थिति में सुधार हो सकेगा। केंद्र सरकार भी कहती रही है कि नये कानूनों का मकसद लोगों को सजा देने के बजाय न्याय दिलाने पर केंद्रित है। विश्वास किया जाना चाहिए कि इन प्रयासों से मुकदमों के निस्तारण में गति आएगी। देश की जनता उम्मीद लगाए बैठी है कि दशकों से लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण हो। जिससे न्यायिक प्रक्रिया से हताश-निराश लोग समझौता करने को बाध्य न हो। विश्वास किया जाना चाहिए कि मुख्य न्यायाधीश की चिंता के बाद न्यायिक प्रक्रिया को सरल-सुगम बनाने के लिये अभिनव पहल हो सकेगी। जिससे आम लोगों की समय पर न्याय मिलने की आस पूरी हो सकेगी।

बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्तापलट और भारत

—निरज कुमार दुबे—



बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में जान-माल और लोकतंत्र को भारी नुकसान के बाद आखिरकार शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट हो ही गया। देश की कमान अब सेना के पास है और उसने अंतरिम सरकार का गठन करवाने की बात कही है। शेख हसीना को सत्ता से हिस्र करने के लिए बांग्लादेश में जिस तरह का अभियान चलाया गया उसने दूसरे इस्लामिक देशों के सत्ताधारियों की नींद उड़ा दी है। शेख हसीना का सत्ता से बाहर होना कहकरपंथियों की बहुत बड़ी जीत है। यह जीत दर्शाती है कि दुनिया भर में हावी होते इस्लामिक कहकरपंथी अब भारत के बंगाल में भी प्रभावी हो रहे हैं। दुनिया में कई इस्लामिक देश उदरवादी माने जाते हैं अब उन्हें यह खतरा सता रहा है कि यदि कहकरपंथी उनके यहां भी हावी हुए तो वर्तमान सत्ताधारियों के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से अभियान चलकर उन्हें शासन से बाहर किया जा सकता है।

जहां तक शेख हसीना की बात है तो उनके शासनकाल में पहली बार देश में हालात इस कदर बेकरार हुए कि उन्हें इस्तीफा देकर अपना देश छोड़कर ही भागना पड़ा। शेख हसीना को खिलाफ इस समय नाराजगी भरे चरम पर पहुँच चुकी थी लेकिन जब वह 2009 का आम चुनाव जीत कर प्रधानमंत्री बनी थी तब उनकी लोकप्रियता देखने लायक थी। 2009 के बांग्लादेश चुनाव के नतीजों से सबसे बड़ा झटका शेख हसीना की मुख्य प्रतिद्वंद्वी खालिदा जिया को नहीं बल्कि कहरपंथी जमात-ए-इस्लामी को लगा था। जमात-ए-इस्लामी वही संगठन है जिसने 1971 के मुक्ति संग्राम में

पाकिस्तान का पक्ष लिया था। खालिदा जिया की सरकार के दौरान आतंकवादी संगठन बांग्लादेश में खूब फले-फूले थे और कहकरपंथियों का वहां बोलबाला हुआ करता था। जमात-ए-इस्लामी की ही उस समय 20 संसद हुआ करते थे। यही नहीं, खालिदा जिया के जमाने में आतंकी तत्व बांग्लादेश की परती का उपयोग करते थे। खिलाफ गतिविधियां चलाने में किया करते थे। उस समय उरुका तत्व कई अन्य उग्रवादी संगठनों के ठिकाने बांग्लादेश में हुआ करते थे। इस संबंध में जब भी भारत सरकार ने तत्कालीन खालिदा सरकार को कार्रवाई के लिए कहा तब-तब खालिदा जिया की सरकार कह देती थी कि भारत की ओर से दी जा रही सूचनाएं गलत हैं।

खालिदा जिया ने सत्ता से हटने के बाद काफी प्रयास किया कि वह दोबारा सरकार में लौट सकें लेकिन जनता ने उन्हें हमेशा खारिज किया। खालिदा जिया धीरे-धीरे मुख्यभार की राजनीति से दूर हो गयीं जिससे ऐसे उरुका और आतंकी तत्वों के

लिए अस्तित्व बनाने का सवाल खड़ा हो गया जोकि खालिदा जिया के शासन की छत्रछाया में पनपते थे। इन तत्वों ने सरकार के विरोध में योजनाबद्ध तरीके से अभियान चलाया और छात्रों को आगे कर वह अपना उदरथ्य हासिल करने में सफल रहे। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वह वहां के लिए तो काफी है ही साथ ही भारत के लिए भी यह मुश्किल बढ़ने वाली बात है। भारत ने हालांकि बांग्लादेश सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी है लेकिन अब देश को चीन और पाकिस्तान की सीमा के अलावा बांग्लादेश सीमा पर भी काफी सावधानी बरतनी होगी। ढाका में दिल्ली सभ्यंक सरकार को नहीं सहन करती है और अफाकी बहार है कि 2009 में शेख हसीना सरकार के आने के बाद से भारत और बांग्लादेश के संबंधों में प्रगाढ़ता आई थी। इससे पहले जब शेख हसीना 1996 से 2001 के बीच सत्ता में थीं तब भी भारत और बांग्लादेश के संबंध बेहतर रहे थे। शेख हसीना ने बांग्लादेश की कमान संभालने के बाद कहकरपंथियों पर लगाम लगाई थी और भारत विरोधी गतिविधियां संचालित कर रहे संगठनों पर भी अंकुश लगाया था। यही नहीं, शेख हसीना बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को भी अस्वस्थ सुरक्षा का पूरा प्रसास दिलाली रखती थीं और उनके बालिक आयोजनों में भी शामिल होतीं थीं। शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद हिंदुओं पर हमले बढ़ने और हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुँचाने जाने की आशंका बलवती हो रही है। पहले ही वहां हिंदुओं पर धैर्य हमले होते रहे हैं ऐसे में अब उनके लिए खतरा और बढ़ गया है।

वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि शेख हसीना ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को भी संकोचते से उभारा था लेकिन यह भी तथ्य है कि हाल के वर्षों में खासकर महामारी के बाद से देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी थी। बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के चलते शेख हसीना को खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही थी। देखा जाये तो बांग्लादेश में

मौजूदा आशाति का कारण सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरियों की संख्या नहीं बढ़ना भी है। उस पर से बांग्लादेश सरकार के हालिया आरक्षण संबंधी फैसले से छात्रों में नाराजगी बढ़ गयी थी। इसके अलावा, बांग्लादेश के कपड़ा कारखाने पूरी दुनिया में मशहूर हैं लेकिन अब यह क्षेत्र सिक्कू रह रहा है जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है। साथ ही बांग्लादेश में महंगाई के 10 प्रतिशत के आसपास बने रहने, बांग्लादेश के विदेशी मुद्रा भंडार के सिक्कूट जाने और देश पर विदेशी कर्ज बढ़ते जाने जैसे कई अन्य कारक भी रहे जोकि शेख हसीना सरकार के खिलाफ आम जनता की नाराजगी बढ़ा रहे थे।

उस पर से जब शेख हसीना ने यह कह दिया कि आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोग छात्र नहीं बल्कि इस्लामिक पार्टी, जमात-ए-इस्लामी और मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के लोग थे तो छात्रों का पूरा आरंभ भड़क गया। इसके बाद शेख हसीना ने और कड़ा रुख कारने हुए कह दिया कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं वे छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी हैं जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं इसलिए सरकार उनसे साथ सहती से निवृत्त होगी। उनके इस बयान के बाद तो आंदोलनरत छात्रों ने आर

पाठ को लाई का मन बना लिया और आखिरकार वह अपने उदरथ्य को हासिल करने में सफल रहे। बांग्लादेश से जो दूधय सामने आ रहे हैं वह दर्शा रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों का महकद सिर्फ सत्ता बदलना नहीं था। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के अलावा और अन्य महत्वपूर्ण इमारतों में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने जो हारकत की है वह दर्शा रही है कि अब देश अराजकतावादियों के हाथ में चला गया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के अलावा से जिस तरह मस्ती करते या संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का बौद्धिकता से तलाश करते हैं। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों को सभ्यना होगा कि मूर्खियों को तोड़ने, सरकारी इमारतों को नुकसान पहुँचाने और किसी देश के विरोध में अभियान चलाने से देश की अर्थव्यवस्था सुधर नहीं जायेगी।

बांग्लादेश में लोकतंत्र के नहीं रहने का सबसे बड़ा खामियाजा यह होगा कि विदेश कर्ज हासिल करने के जो प्रयास किये जा रहे थे, या बांग्लादेश को आने वाले था, अब वह बाकि हो जायेगा। बांग्लादेश में लोकतंत्र के नहीं रहने का खामियाजा यह होगा कि विदेशी सरकारों उसकी मदद करने से कारागीरी। दुनिया का कोई भी लोकतांत्रिक देश दूसरे देश की सरकार से ही बाधोचित करने या कोई कार करने को बरीयाता देता है। सैन्य नियंत्रण वाले देशों से लोकतांत्रिक देश अस्वर दूरी बनाये रखते हैं।

बहरहाल, बांग्लादेश की सेना और राष्ट्रपति को चाहिए कि जल्द से जल्द अंतरिम सरकार का गठन किया जाये और समय हो तो नये चुनाव कराये जाए। यह सर्वविधित है कि हिंसा किसी मसले का हल नहीं है, लूटपाट और उरुकात से देश को नुकसान ही होगा और पिछले वर्षों में अंगूठे बन्दे के लिए जो शहनाह की गयी थी उस पर भी पानी फिरा जायेगा। इसलिए समय की आवश्यकता है कि बांग्लादेश एकजुट होकर इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकले।

जरूरतों के हिसाब से प्रशिक्षित हों युवा



—सुरेश सेठ—

दुनिया तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। कामकाज के तरीके तेज हैं डिजिटल और स्वचालित हो रहे हैं। रोबोटिक शक्ति इस्का आधार बन रही है। कृत्रिम भ्रमा भी मुख्य सशक्तियों के रूप में उभर रही है। यानी भारत में उद्यमान, निवेश और खेती-किसानी के तरीके भी बदलेंगे।

विशेषज्ञों के अनुसार अगले दस सालों में कामकाज के घंटों और नौकी करने के तौर-तरीकों में परिवर्तन आएगा। एआई और रोबोटिक्स के चलते स्थायी व्यवस्था की जगह निग अर्थव्यवस्था सामने आएगी। इसमें जरूरत के अनुसार अस्थायी कर्मचारियों को काम पर रखने का चलन बढ़ेगा। इससे संकट के अतिरिक्त नौकरियों की व्यवस्था के अतिरिक्त कर्मचारी संविदा के आधार पर विभिन्न सेक्टर-कंपनियों में एक साथ कई जिम्मेदारियां सभल सकेंगे। इसका असर डिजिटल और इंटरनेट की दुनिया में अभी से दिखने लगा है। आईटी एक्सपर्ट डॉक क्रॉम होम करते हुए एक साफ कहें कंपनियों का काम संभल रहे हैं। पिछले दिनों एक अरबना सामने आया था कि काम के घंटे 10 से 14 कर दिए जाएं, क्योंकि आईटी क्रांति का सामना इसी तरह से किया जा सकेगा। बहरहाल, कामकाजी दुनिया की हकीकत बदल रही है।



इसके द्वारा अगले पांच साल में 4.1 करोड़ नौकरियों को विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे रोजगार की दुनिया में खुद को अनुकूलित कर सकें।

देश में आज भी आधी आबादी से काम खेतीबाड़ी में लगी हुई है। प्रश्न है कि वहां से सकल घरेलू अंश में केवल 16 प्रतिशत का योगदान ही क्यों मिल रहा है? आंकड़ें बताते हैं कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर बढ़ी है। इसका अतिरिक्त, ऐसे बेरोजगार भी हैं जो पारंपरिक तरीके से अपनी पैतृक खेतीबाड़ी के धंधे में लगे रहते हैं, लेकिन देश की निवगत आय में उनका कोई योगदान नहीं है। इस अनुपयोगी युवा शक्ति का इस्तेमाल किसी ऐसे कर्मलिक क्षेत्र में होना चाहिए जो उन्हें ग्रामीण स्तर पर ही वहीं काम उपलब्ध करावे द। लघु और कुटीर उद्योगों का विकास और फसलों को पूर्ण रूप से तैयार करके सीधे मंडी में बेचना भी एक समाधान हो सकता है। बजटिय घोषणाओं में आने वाले बड़े अखिल भारतीय सहकारी अभियान चलाने का वादा है। इसका अंतर्गत इन सभी लोगों को कामगार मिलेगा। लघु-कुटीर उद्योगों की बातें तो होती हैं लेकिन लाल डोरा क्षेत्र में भी ग्रामीण युवा शक्ति के स्थान पर शहरी निवेशक ही प्रवेश करना जाना आता है।

निरसंह, जब निजी क्षेत्र का विकास होगा और नये कारखाने खुलेंगे या फसलों पर आधारित छोटे उद्योग बढ़ेंगे, तो लोगों को स्वाम्यधिक रूप

कोटे के अंदर कोटे का सुप्रीम निर्णय



—डॉ. आशीष वशिष्ठ—

सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक अहम फैसले में यह साफ कर दिया है कि राज्यों को आरक्षण व्यवस्था में कोटे के भीतर भी कोटा बनाने का अधिकार है। यानी राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति व जनजातित वं में भी आरक्षण के लिए अलग-अलग श्रेणियां बना सकती हैं। यह अधिकार अभी तक राष्ट्रपति के पास ही सुनिश्चित था। संसद में ही प्रस्ताव पारित कर, किसी भी जाति को, आरक्षण के दायरे में लाया जा सकता था अथवा जाति को आरक्षण से बाहर भी किया जा सकता था।



इस फैसले के बाद इन वर्गों में हाशिर पर पड़ी जातियों को आरक्षण का फायदा मिलने की उम्मीद है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि यह बात भी लातारार उठाई जा रही थी कि राष्ट्रपति अस्वर नहीं मिलने के कारण सुनिश्चित अजा-जजा वर्ग में भी ऐसी कई जातियां हैं जो सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग से उभर नहीं पा रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर राजनीतिक दल, समाजिक कार्यकर्ता और अन्य समूह को आश्चर्य में बंदते दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक दल अनेक नुकसान के हिसाब से इन फैसले पर बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा और काँग्रेस जैसे बड़े दलों ने इस मुद्दे पर लगामा चुपी खाए रखी हैं। राजनीतिक चरम से इतर देखें तो संविधान पीठ का फैसला सामाजिक न्याय के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है।

वर्तमान में दलित और आदिवासीयों को शिक्षा और नौकरियों में क्रमशः 15 फीस और 7.5 फीस की आरक्षण हासिल है। संविधान पीठ के दो कथन महत्वपूर्ण हैं। एक, एएसटी-एएसटी के कोटे में कुछ जातियों को उप-वर्गीकरण करने से संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 341 का उल्लंघन नहीं होता।

पहचान करने पर जोर दिया गया, जिन्हें कोटा से लाभ नहीं मिला। अंग्रेजों ने 101 जातियों को चार श्रेणियों में विभाजित करने की सिफारिश की।

2006 में तब की केंद्र सरकार ने सब कटेरीय के लिए एक फैसल बनाने का निर्णय लिया। 2007 में ऐसा मेहरा को इस फैसला का अंश बनाया गया। 2007 में ही बिहार के महादलित फैसल ने भी ऐसी सिफारिश की। इसमें कहा गया कि एएसटी की 18 जातियों को अलग-अलग जातियों के रूप में माना जाना चाहिए। 2008 में तब की केंद्र सरकार को रिपोर्ट सीपी। 2009 में यूनानाइटेड अंध प्रदेश से सीएम वॉइस राजेश रेड्डी ने केंद्र को पत्र लिख इसे स्पष्ट निम्न गारंटी देने की मांग की। 2014 में संसलाना के बनने के बाद केंद्रीय ने एक प्रस्ताव पेश कर केंद्र से सब कटेरीय बनाने की मांग की। 2023 में सिंकरवादीयों की एक सभा में पीएम मोदी ने कहा कि कोटे के अंदर कोटे का सार्थक करने। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया।

ताजा फैसला पंजाब को दल, दरअसल पंजाब सरकार ने 2006 में संसलाना बनाया था कि राज्य में एएसटी-एएसटी आरक्षण में 50 फीस की आरक्षण, पहली प्राथमिकता के तहत, वास्तविक और मशहूरी शिरावों को मिलेगा। पंजाब उच्च न्यायालय ने 2010 में इसे रद्द कर दिया था। उच्च खिलाफ पंजाब सरकार सर्वोच्च अदालत पहुँच गयी। इन समय संसलाना के पीठ ने अलग-अलग अनुच्छेद की व्याख्या स्पष्ट की है और कोटे के अर्धीय को अलग-अलग को फैसला दिया है। डाटा के आधार पर यह कोटा बदलता रहस्य। यही सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी एक वर्ग को 100 फीस की आरक्षण दे दिया जाए। राज्य सरकारें नहीं बना से उप-वर्गीकरण करनी बाकी जातियों के बीच उन जातियों की

